



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257814
CG-DL-E-12102024-257814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4036]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4036]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4399(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड', गांधीनगर (पैन AAALG5041P), जो कि गुजरात सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात् :

- (क) सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान;
- (ख) गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 1978/गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेंज;
- (ग) स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों/उद्योगों से एकत्रित जल शुल्क (गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ);
- (घ) पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान से प्राप्तियां;
- (ङ) अन्य आय जैसे जांच शुल्क, किराया शुल्क, निविदा अनुसूची की बिक्री और गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 1978 के तहत प्राप्त किराया; और
- (च) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड', गांधीनगर—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 से संगत निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी और यह वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025 और 2025-2026 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 108 /2024/फा. सं. 300196/15/2021-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4399(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Gujarat Water Supply and Sewerage Board', Gandhinagar (PAN: AAALG5041P), a Board constituted by the Government of Gujarat in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

- (a) Grant received from Government, Local Bodies and Other Government Agencies;
- (b) Centage at rates prescribed by the Gujarat Water Supply and Sewerage Board Act, 1978/Government of Gujarat;
- (c) Water charges (tariff fixed by the Government of Gujarat) collected from local bodies/village panchayats/ industries;
- (d) Receipts from Pension and gratuity contribution;
- (e) Other incomes such as investigation charges, Hire Charges, Sale of Tender Schedule and Rent received under the Gujarat Water Supply and Sewerage Board Act, 1978; and
- (f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Water Supply and Sewerage Board, Gandhinagar—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2021-2022 and 2022-2023 and shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027 relevant for the financial years 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026 respectively.

[Notification No. 108 /2024/ F. No. 300196/15/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.